बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 205 ● नई दिल्ली ● सोमवार 01 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिसंबर तक शुरू होंगे मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर, क्या आपके घर के पास भी बन रहा है स्टेशन?

नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहरों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए मेट्रो विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक मेट्रो के तीन और कॉरिडोर शुरू होने की उम्मीद है। इसमें मजेंटा लाइन का जनकपुरी पश्चिम- आरके आश्रम मार्ग विस्तार के दो हिस्से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक और मजलिस पार्क से आरके आश्रम मार्ग के साथ ही गोल्डन लाइन के एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर शामिल है। इनके शुरू होने से मेट्रो के नेटवर्क में लगभग 36 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर को दी श्रद्धांजलि, कहा- उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और जनकल्याण के प्रति उनके समर्पण के लिए उन्हें गहरे सम्मान के साथ याद करता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। नरेंद्र मोदी ने मालवा साम्राय की पूर्व शासिका अहिल्याबाई होलकर के जीवन को सुशासन, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने हमेशा साहस और कर्तव्यनिष्ठा के साथ नेतृत्व किया। उनके द्वारा समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती

पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूरा देश उन्हें गहरे सम्मान और प्रशंसा के साथ याद करता है।

अहिल्याबाई होलकर का योगदान अतुलनीय- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में पवित्र मंदिरों और तीर्थस्थलों के पुनर्निर्माण से लेकर सभी के लिए न्याय और कल्याण सुनिश्चित करने तक अहिल्याबाई होलकर का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक चेतना को और मजबूत करने का काम किया। समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा।

कौन थीं अहिल्याबाई होलकर?

अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और 13 अगस्त 1795 को उनका निधन हुआ। वह मालवा साम्राय की रानी थीं और उन्हें भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है। 18वीं शताब्दी में मालवा की महारानी के रूप में उन्होंने धर्म का संदेश फैलाने और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान साल 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और मरम्मत कराना था। इसके अलावा उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में कई धर्मशालाओं, घाटों और मंदिरों का निर्माण कराया था। उनके शासनकाल को शांति और न्याय के लिए जाना जाता है।

वसंत कुंज हाईराइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट को दिल्ली हाई कोर्ट की मंजूरी, निवासियों की याचिका खारिज

नई दिल्ली।

दिल्ली हाई कोर्ट ने वसंत कुंज में एक सामूहिक आवास परियोजना को मंजूरी देते हुए स्थानीय निवासी कल्याण संघ और एक स्कूल की याचिका खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की मास्टर प्लान में इमारतों की ऊंचाई को स्थायी रूप से निर्धारित करने का प्रविधान नहीं है और नई इमारतों को आसपास के फ्लैटों पर लागू पुरानी ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ऊंची इमारत क्षेत्र के कम ऊंचाई वाले स्वरूप को बिगाड़ देगी और नियोजन मानदंडों का उल्लंघन करेगी। पीठ ने कहा कि दिल्ली में भूमि सीमित है और यहां निरंतर जनसंख्या दबाव और लगातर आवासीय आवास की मांग बढ़ती जा रही है।

हाई कोर्ट ने कहा- दिल्ली में भूमि सीमित

वसंत कुंज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और मेसोनिक पब्लिक स्कूल ने तर्क दिया कि अधिकारी मौजूदा इमारतों से लगभग तीन गुना ऊंची टावरों की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि, कोर्ट ने माना कि अनुरूपता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक नई संरचना को पड़ोसी इमारतों की सटीक ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने लगभग 30-33 मीटर ऊंची परियोजना को चुनौती दी थी थी। यह प्रोजेक्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की स्व-वित्तपोषित योजनाओं के 12 मीटर ऊंचाई वाले फ्लैटों के बीच में थी।

हाई कोर्ट ने और क्या कहा?

वसंत कुंज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और मेसोनिक पब्लिक स्कूल ने तर्क दिया कि यह ऊंचाई में अचानक बढ़ोतरी वर्ष 2018 के डीडीए नियमों का उल्लंघन है और अधिकारी मौजूदा इमारतों से लगभग तीन गुना ऊंचे टावरों को बनाने की अनुमति नहीं दे सकते।

एसोसिएशन और स्कूल ने एमपीडी-2021, पर्यावरणीय और नागरिक मानदंडों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। हालांकि, अदालत ने माना कि अनुरूपता का मतलब यह नहीं है कि हर नई इमारत की ऊंचाई आस-पास की इमारतों की ऊंचाई के बिल्कुल बराबर हो। साथ ही अदालत ने डीडीए ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि वसंत कुंज योजना के बड़े दायरे के भीतर पहले से ही इसी तरह की बहुमंजिला इमारतें मौजूद हैं। पीठ ने डीडीए की तकनीकी समिति द्वारा दिए गए उन स्पष्टीकरणों पर भरोसा किया, जिनमें कहा गया था कि दिल्ली का मास्टर प्लान - 2021 (एमपीडी-2021) ऊंचाई पर ऐसी कोई अलग से सीमा नहीं लगाता, जैसा कि एसोसिएशन और स्कूल ने दावा किया था।

आग लगने पर कुआं खोदने की तैयारी- दिल्ली की प्यास बुझाने पर सरकार ने किया घंटों मंथन, फरमान जारी; मुसीबत तारी

दिल्ली । भीषण गर्मी के बीच दिल्लीवासियों की प्यास बुझाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार घंटों मंथन कर रणनीति के तहत काम कर रही है। अब एक-एक बूंद पानी का हिसाब रखा जा रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल मंत्री, दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक कर मंथन किया कि सीमित संसाधनों के बीच राजधानी के हर इलाके और हर घर तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। इस दौरान जल प्रबंधन, रिसाव रोकने, शिकायतों के त्वरित निस्तारण, टैंकर आपूर्ति बढ़ाने और जल संरक्षण के उपायों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी इलाके में पानी की समस्या को हल्के में न लिया जाए। इसमें इस बात पर मंथन किया गया कि बढ़ती गर्मी और सीमित जल उपलब्धता के बीच कैसे हर दिल्लीवासी तक पर्याप्त पानी पहुंचाया जाए। बैठक में जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सदस्य अजय महावर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। छोटे टैंकरों की संख्या बढ़ा रही सरकार : भीषण गर्मी के बीच उत्पन्न हालात से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का पूरा तंत्र मैदान में उतर गया है। अधिकारियों के मुताबिक 980 से अधिक जल टैंकर रोजाना 6,000 से यादा फेरे लगा रहे हैं। घनी आबादी और संकरी गलियों वाले इलाकों में छोटे टैंकरों की भी तैनाती की गई है, ताकि पानी उन जगहों तक भी पहुंच सके जहां बड़े वाहन नहीं जा सकते। जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए यमुना खादर क्षेत्र में अतिरिक्त बोरवेल लगाए गए हैं। इससे प्रतिदिन 10.5 एमजीडी अतिरिक्त जल उत्पादन क्षमता बढ़ी है। सरकार का मानना है कि यह अतिरिक्त पानी उन इलाकों में राहत पहुंचाने में मदद करेगा जहां मांग अधिक और आपूर्ति कम है। यमुना में वजीराबाद के पास जल उपलब्धता प्रभावित होने से राजधानी की जल आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत की।

फर्जी चेक से की थी 5.20 करोड़ की ठगी, 6 साल बाद फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी चेक के जरिए अमिटी यूनिवर्सिटी के खाते से 5.20 करोड़ रुपये की बड़ी ठगी करने वाले आरोपी को 6 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के 58 वर्षीय सुदामा नरवारे के रूप में हुई है, जिसे अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी थी. मामला साल 2019 का है. आरोपी ने अमिटी यूनिवर्सिटी के नाम से जारी तीन फर्जी चेक बैंक में जमा किए. इनमें से दो चेक क्लियर हो गए और कुल 5.20 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए. तीसरे चेक को समय रहते रोक लिया गया. जांच में पता चला कि 2.50 करोड़ रुपये गुजरात के वडोदरा स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के खाते में और 2.70 करोड़ रुपये बैतूल स्थित «मां ताप्ती मानव सेवा संस्थान» नामक एनजीओ के खाते में जमा किए गए थे. बाद में इस रकम को शेल कंपनियों और अन्य खातों में भेज दिया गया. सुदामा नरवारे उक्त एनजीओ का सचिव और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था. पुलिस के अनुसार उसने एनजीओ खाते में आए 2.70 करोड़ रुपये में से करीब 2.08 करोड़ रुपये अन्य आरोपियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. दिल्ली पुलिस की EOW टीम ने आरोपी की लंबे समय से तलाश की थी.

गीले कचरे से बदलेगी भारत की अर्थव्यवस्था, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ होंगे खत्म

नई दिल्ली।

भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में दिल्ली और एनसीआर सहित अन्य शहरों से निकलने वाला गीला कचरा (आर्गेनिक वेस्ट) भविष्य में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार बनने जा रहा है। थिंक-टैंक काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की नई रिपोर्ट के अनुसार यदि देश में सही नीतियां और ग्रीन ट्रांजिशन माडल अपनाया जाए तो अगले 20 वर्ष तक गीले कचरे के प्रबंधन का बाजार करीब 5.1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा। यह देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ-साथ शहरों की सूरत बदलने की ताकत भी रखता है।

कचरा नहीं, यह है क्लीन एनर्जी और कमाई का जरिया

रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के शहरों में निकलने वाले कुल ठोस कचरे का लगभग आधा हिस्सा गीला कचरा (किचन, सब्जी मंडियों और बागवानी का कचरा) होता है। वर्तमान में देश में इसे प्रोसेस करने के लिए 96 प्रतिशत कंपोस्टिंग (खाद बनाना) और सिर्फ चार प्रतिशत बायोमेथनेशन (बायो-गैस बनाना) तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इस माडल को तेजी से आधुनिक और आटोमेटेड बायोमेथनेशन की तरफ ले जाते हैं, तो इससे न केवल रासायनिक उर्वरकों (केमिकल फर्टिलाइजर्स) पर निर्भरता कम होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) का उत्पादन होगा, जो भारत के महंगे ईंधन आयात बिल को कम करेगा।

दिल्ली के लिए इसलिए है यह खास

राजधानी इस समय कचरे के ढेरों (गाजीपुर-भलस्वा-ओखला) और भीषण गर्मी से जूझ रही है। यह माडल दिल्ली के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 पहले ही जीरो वेस्ट और सर्कुलर इकोनामी की वकालत करता है।

गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में लगे कचरे के पहाड़ों को खत्म करने में यह तकनीक रीढ़ साबित हो सकती है। कचरे के सड़ने से निकलने वाली मीथेन गैस दिल्ली में स्थानीय तापमान बढ़ाकर थर्मल हाट स्पाट पैदा करती है, जिससे जानलेवा लू का प्रकोप बढ़ता है। हाल ही में दिल्ली सचिवालय से रवाना की गई हीटवेव बैन जैसी पहल को भी इस तकनीक से सीधे मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, नरेला जैसे नए अर्बन क्लस्टरों और डीडीए के ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) प्रोजेक्ट में आन-साइट बायोगैस प्लांट लगाकर कचरे को सीधे बिजली और गैस में बदला जा सकेगा। रिपोर्ट की मानें तो पीपीपी माडल, ग्रीन बांड और नगर निगमों द्वारा कचरा पृथकरण को कड़ाई से लागू कर राजधानी समेत पूरे देश को कचरा-मुक्त और आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा सकता है।

गोल्डन लाइन का 75 फीसदी काम पूरा, फिर भी डेडलाइन पर संकट

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो के फेज-4 की सबसे अहम परियोजनाओं में शामिल गोल्डन लाइन कॉरिडोर तय समयसीमा से पीछे चलता नजर आ रहा है. तुगलकाबाद से एरोसिटी के बीच बन रहे इस मेट्रो मार्ग का निर्माण कार्य अभी पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ सका है, जिससे इस साल के भीतर इसके पूरा होने की संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है. ऐसे में दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद लगाए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है.

एक चौथाई से यादा काम अब भी अधूरा

करीब 23.6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 15 नए मेट्रो स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं. परियोजना का अधिकांश हिस्सा भूमिगत बनाया जा रहा है, जबकि महरौली-बदरपुर रोड पर खानपुर तिराहे से संगम विहार तक का हिस्सा डबल डेकर संरचना के रूप में तैयार किया जा रहा है. निर्माण की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी, लेकिन कोविड और भूमि उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों ने इसकी गति को प्रभावित किया. वर्तमान स्थिति में परियोजना का लगभग 26 प्रतिशत कार्य शेष है, जिससे अगले छह महीनों में इसे पूरा करना कठिन माना जा रहा है.

सिविल कार्य में प्रगति, लेकिन

करीब 23.6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 15 नए मेट्रो स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं. परियोजना का अधिकांश हिस्सा भूमिगत बनाया जा रहा है, जबकि महरौली-बदरपुर रोड पर खानपुर तिराहे से संगम विहार तक का हिस्सा डबल डेकर संरचना के रूप में तैयार किया जा रहा है.

लक्ष्य अब भी दूर

दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार अप्रैल तक कॉरिडोर का सिविल निर्माण कार्य 78.11 प्रतिशत तक पहुंच चुका है. हालांकि समग्र परियोजना प्रगति 73.25 प्रतिशत दर्ज की गई है. यह अंतर दर्शाता है कि कई तकनीकी और सिस्टम आधारित कार्य अभी पूरे होने बाकी हैं. इसी कारण परिचालन शुरू होने की समयसीमा आगे खिसकने की आशंका बढ़ गई है.

चरणबद्ध तरीके से शुरू हो सकती है सेवाएं

डीएमआरसी अब इस कॉरिडोर को वर्ष 2026 के अंत तक अलग-अलग चरणों में यात्रियों के लिए खोलने की योजना पर काम कर रहा है. यदि निर्माण और परीक्षण कार्य तय गति से आगे बढ़ते हैं तो कुछ हिस्सों में पहले संचालन शुरू किया जा सकता है, जबकि पूरे कॉरिडोर के लिए यात्रियों को अतिरिक्त समय का इंतजार करना होगा.

फेज-5 में और बढ़ेगा गोल्डन लाइन का दायरा

गोल्डन लाइन को भविष्य में और विस्तारित करने की तैयारी भी की जा रही है. प्रस्तावित विस्तार के तहत एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक तथा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक मेट्रो नेटवर्क को आगे बढ़ाया जाएगा. यह विस्तार फेज-5ए परियोजना का हिस्सा होगा और इसे वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

वैश्विक हालात भी बन रहे चुनौती

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ रहा है. मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण कच्चे माल, मशीनरी और मानव संसाधनों की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. उन्होंने संकेत दिया कि यदि परिस्थितियां प्रतिकूल बनी रहती हैं तो परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों और समयसीमा की समीक्षा की जा सकती है.

गोल्डन लाइन को फेज-4 की सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजनाओं में गिना जा रहा है. इसके शुरू होने से दक्षिण दिल्ली, संगम विहार, खानपुर और एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आवागमन काफी आसान होने की उम्मीद है. हालांकि फिलहाल निर्माण की मौजूदा रफ्तार यह संकेत दे रही है कि यात्रियों को इस नई मेट्रो लाइन की सुविधा पाने के लिए अनुमान से अधिक इंतजार करना पड़ सकता है.

करीब 23.6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 15 नए मेट्रो स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं. परियोजना का अधिकांश हिस्सा भूमिगत बनाया जा रहा है, जबकि महरौली-बदरपुर रोड पर खानपुर तिराहे से संगम विहार तक का हिस्सा डबल डेकर संरचना के रूप में तैयार किया जा रहा है।

तंबाकू,नशे का बदलता स्वरूप

वैश्विक स्तरपर हर वर्ष 31 मई को पूरी दुनियाँ में वर्ल्ड नो टोबैको अर्थात विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष इस अवसर पर भाषण होते हैं, शपथ ली जाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं और तंबाकू के दुष्परिणामों पर चर्चा होती हैलेकिन एक कड़वा प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा है,क्या केवल एक दिन का यह प्रतीकात्मक आयोजन उस भयावह महामारी को रोक सकता है जो प्रतिदिन लाखों लोगों के शरीर में कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों की घातक बीमारियों का जहर घोल रहे है भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में नागरिकता कानून,आरक्षण,भ्रष्टाचार,किसानों की समस्याएं,भाषा विवाद, जल-जंगल-जमीन के प्रश्न, मंडल -कमंडल की राजनीति, जनलोकपाल आंदोलन, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे मुद्दे बड़े जनांदोलनों का रूप ले चुके हैं।सड़कों पर लाखों लोग उतरते हैं,संसद और विधान सभाओं में बहस होती है, सरकारें झुकती है और नीतियां बदलती हैंपरंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र इस आर्टिकल का माध्यम से शासन प्रशासन व समाज से पूछना चाहता हूं कि तंबाकू, जो हर वर्ष लाखों परिवारों को उजाड़ देता है, आज भी उतना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन क्यों नहीं बन पाया जब किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य तंबाकूजनित कैंसर से मरता है, जब किसी बच्चे का पिता गुटखा या सिगरेट के कारण असमय दुनियाँ छोड़ देता है, जब किसी माँ की आंखों के सामने उसका जवान बेटा निकोटीन की लत का शिकार होकर जीवन हार जाता है, तब यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह जाती,बल्कि यह राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाती है। मेरे अपने एक निकट संबंधी की मृत्यु भी तंबाकूजनित कैंसर के कारण हुई। ऐसे हजारों-लाखों परिवारों का दर्द यह संकेत देता है कि अब तंबाकू निषेध को केवल स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। साथियों बात अगर हम तंबाकू व नशीली चीजों के खिलाफ़ बहुत बड़े आंदोलन की करें तो तंबाकू निषेध आंदोलन को इस तरह के आंदोलन समकक्ष बनाने की जरूरत है जैसे भारतीय लोकतंत्र का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब किसी मुद्दे को जनआंदोलन का रूप मिला, तब उसने सरकारों की नीतियों,कानूनों और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया। वर्ष 1974 का जेपी आंदोलन (संपूर्ण क्रांति आंदोलन), वर्ष 1990 का मंडल आयोग आरक्षण आंदोलन 1980 और 1990 के दशक का राम जन्मभूमि आंदोलन,वर्ष 2011 का अन्ना हजारे के नेतृत्व वाला भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकपाल आंदोलन, वर्ष 2019- 20 का नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी आंदोलन, वर्ष 2020-21 का कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान आंदोलन, वर्ष 2015 और उसके बाद विभिन्न राज्यों में हुए पटीदार आरक्षण आंदोलन,जाट आरक्षण आंदोलन, मराठा आरक्षण आंदोलन, गुर्जर आरक्षण आंदोलन तथा हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े आंदोलनों ने यह सिद्ध किया है कि संगठित जनदबाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।इन आंदोलनों ने न केवल राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया बल्कि सरकारों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए भी बाध्य किया। आज 30 मई 2026 से महाराष्ट्र में शुरू हुआ मनोहर जरांगे का मराठा आरक्षण आंदोलन सहित देश के अनेक हिस्सों में सामाजिक, जातीय और आरक्षण से जुड़े आंदोलन लगातार सुर्खियों में हैं, जो यह दर्शाते हैं कि जनता जब किसी विषय को अपने अस्तित्व, अधिकार या भविष्य से जोड़ लेती है तो वह एक विशाल जनशक्ति का रूप धारण कर लेता है। तो फिर तंबाकू व नशीली चीजों के विरुद्ध ऐसा आंदोलन किसी राजनीतिक सामाजिक या व्यक्तिगत संगठन में क्यों नहीं उठाया है यह विचारणीय प्रश्न है साथियों, पिछले एक दशक में नशे का स्वरूप तेजी से बदला है। कभी बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की पुड़िया तक सीमित रहने वाला यह कारोबार अब अत्याधुनिक तकनीक के आवरण में युवाओं के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ई- सिगरेट, वेप्स, निकोटीन पॉड्स, फ्लेवर्ड हुक्के, निकोटीन पाउच और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान उपकरण आधुनिक जीवनशैली के प्रतीक के रूप में प्रचारित किए जा रहे हैं। तंबाकू उद्योग ने समझ लिया है कि यदि उसे नई पीढ़ी को अपने जाल में फंसाना है तो उत्पाद का स्वरूप बदलना होगा। इसलिए आज कई वेपिंग उपकरण पेन ड्राइव, स्मार्ट गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्टाइलिश एक्सेसरी जैसे दिखाई देते हैं। किशोर और युवा इन्हें आधुनिकता, स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक समझने लगते हैं। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, वनीला, मिंट और अन्य आकर्षक फ्लेवर के माध्यम से निकोटीन को मीठे जहर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।यह रणनीति केवल व्यापारिकनहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है,क्योंकि स्वाद और आकर्षण के माध्यम से लत को आसान बनाया जाता है। साथियों, सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन आधुनिक उत्पादों को अक्सर पारंपरिक सिगरेट से कम हानिकारक बताने का भ्रम फैलाया जाता है।अनेक युवा यह मान लेते हैं कि वेपिंग सुरक्षित है,जबकि वैज्ञानिक अध्ययनों ने संकेत दिया है कि ई-सिगरेट से निकलने वाला एयरोसोल निकोटीन सहित अनेक हानिकारक रसायनों से भरा होता है। निकोटीन स्वयं अत्यधिक नशे की लत पैदा करने वाला पदार्थ है। इसके अतिरिक्त कई उपकरणों में प्रयुक्त धातुओं, रसायनों और अन्य तत्वों के दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी शोध का विषय है। इसलिए यह कहना कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान पूरी तरह सुरक्षित है, वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा।वास्तव में यह नशे का नया मुखौटा है,जिसका उद्देश्य युवाओं को आकर्षित करना और बाजार का विस्तार करना है।तंबाकू और निकोटीन की इस महामारी का सबसे भयावह पक्ष यह है कि इसका शिकार केवल सेवन करने वाला व्यक्ति ही नहीं होता।पैसिव स्मोकिंग या अप्रत्यक्ष धूम्रपान उन लाखों निर्दोष लोगों की जान ले रहा है जिन्होंने कभी सिगरेट या तंबाकू को हाथ तक नहीं लगाया। घरों, कार्यालयों, रेस्तरां, सार्वजनिक स्थलों और वाहनों में छोड़ा गया धुआं आसपास मौजूद लोगों के शरीर में प्रवेश करता है।

निकाय चुनाव - पंजाब का जनादेश

पंजाब की सियासत में स्थानीय निकाय चुनाव एक इबारत की तरह दर्ज हुए हैं। जिसमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी 102 नगर निकायों के चुनाव में 925 सीटें जीतने के साथ पहले नम्बर पर रही जबकि कांग्रेस 374 सीटें जीतकर दूसरे नम्बर पर रही है। शिरोमणि अकाली दल 189 सीटों के साथ तीसरे नम्बर पर रहा है, जबकि भाजपा चौथे नम्बर पर रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 248 सीटों पर विजय हासिल कर सबको चौंका दिया है। आम धारणा यही है कि जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होती है, स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाता उसी पार्टी को वोट दे देते हैं। पंजाब के मतदाताओं ने भी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को जिताकर डबल इंजन की सरकारों की धारणा को पुख्ता बनाते हुए जनादेश दिया। शहरों की सरकार चुनने के लिए स्थानीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले गए थे और सारा का सारा चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों को सामने रखते हुए लड़ा गया। चुनावी मुद्दे भी वही रहे जो 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में रहने वाले हैं। 8 नगर निगमों में से आप ने मोहाली, बरनाला, बटाला, मोगा और बठिंडा नगर निगमों पर कब्जा जमा लिया, जबकि कांग्रेस कपूरथला नगर निगम और भाजपा ने अबोहर नगर निगम जीता। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले पठानकोट नगर निगम में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत से यह स्पष्ट है कि पंजाब के लोगों में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार के कामकाज को बेहतर मानते हुए उस पर मोहर लगा दी है। पंजाब के जनादेश का अर्थ यही है कि भगवंत मान सरकार द्वारा बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, महिलाओं को हर माह धन और नशों के विरुद्ध सरकार के अभियान और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को सराहा है। इस तरह मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अग्निपरीक्षा पास कर ली है। विपक्ष कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियां राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, गैंगस्टरों की बढ़ती वारदातें, हैंड ग्रेनेड हमलों और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर शोर-शराबा मचाती रहीं लेकिन इनका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आप पार्टी के बारे में पहले कहा जाता था कि नई पार्टी है पंजाब के शहरों ने उन्हें मौका दे दिया लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों के जनादेश ने बड़ा संदेश यह दिया कि पार्टी अब केवल शहरियों की पसंद नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका जनाधार काफी बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं के क्षेत्रों में जबरदस्त सेंधमारी की है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरेन्द्र सिंह राजा वड़िंग के गढ़ माने गए गिदड़बाहा में आप को जबरदस्त जीत हासिल हुई। शिरोमणि अकाली दल के गढ़ बठिंडा में भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। पंथक सीट आनंदपुर साहिब में भी आप पार्टी ने झाड़ू फेर दिया। हाल ही में पंजाब भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए केवल सिंह ढिल्लों के क्षेत्र बरनाला में भी आप पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा जबकि शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को भी नुकसान हुआ। कांग्रेस और शिअद के प्रदर्शन का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों दलों ने लंबे समय तक पंजाब सूबे की सत्ता को संभाला है। ऐसी स्थिति में निकाय चुनाव में इन दलों के ऐसे हश्र की उम्मीद नहीं थी, वो भी तब जब पिछले साढ़े चार साल से पार्टी के आला नेता आप सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए थे। इन दलों की घेराबंदी ध्वस्त हुई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 में से 7 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस इस बात का दावा कर रही थी कि उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आप की आंधी (117 में से 92 सीटों पर जीत) को रोक दिया है। आला नेता भी शहरी और ग्रामीण मतदाताओं पर पार्टी की पकड़ को मजबूत बता रहे थे। मगर साल 2026 के निकाय चुनाव के नतीजों ने तस्वीर ही बदल दी। शिरोमणि अकाली दल के दोफाड़ होने से उसकी पंथक वोट बंट चुकी है और कांग्रेस अभी भी गुटबाजी का शिकार है। यद्यपि चुनावों में भाजपा को ज्यादा सीटें हासिल नहीं हुई लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा पंजाब में लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है। वर्ष 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा 2215 में से केवल 49 सीटें जीत पाई थी लेकिन इस बार उसने अपनी सधी हुई राजनीति के चलते 167 सीटें जीत ली है। विजयी हुए निर्दलीय उम्मीदवारों में डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे और अकाली दल (पुनर्सृजित) के समर्थित उम्मीदवार भी है। चुनाव परिणामों ने संकेत दे दिए हैं कि अगामी विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होंगे। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के चुनावी गठबंधन की सम्भावनाएं तलाशी जा रही हैं। चुनावी गठबंधन से पहले केन्द्र की मोदी सरकार को और भाजपा हाईकमान को किसानों के लम्बित मुद्दों और शिरोमणि अकाली दल की पंथक मांगों के संबंध में ठोस कदम उठाने होंगे तभी गठबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बना पाएगा। कांग्रेस को भी अपनी पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल करने होंगे। देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रणनीति को किस प्रकार धार देती हैं। आम आदमी पार्टी में भगवंत मान का सियासी कद बढ़ गया है। पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल केन्द्र को जमकर निशाना बना रहे हैं। देखना होगा कि विधानसभा चुनावों में

सम्पादकीय...

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट केवल एक न्यायालय नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान का संरक्षक और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक भी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिनका प्रभाव सीधे आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि यदि किसी मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रखा गया है तो उसे तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि वर्षों तक फैसले लंबित रहने से लोगों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान मानी जाती है। कहावत भी बड़ी मशहूर है न्याय में देरी, अन्याय है) दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय सड़क दुर्घटनाओं और चिकित्सा सेवाओं से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय पर ट्रामा केयर और आपातकालीन इलाज प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारत में हर वर्ष हजारों लोग केवल इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलती। यह निर्णय मानव जीवन की गरिमा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय निष्पक्ष चुनावों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया का समर्थन किया है। लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों। यदि मतदाता सूची सही होगी तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु जैसे मामलों में अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधों को अत्यंत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। यह निर्णय महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका की संवेदनशीलता कोदर्शाता है। इन सभी निर्णयों को देखकर एक बात स्पष्ट होती है कि सुप्रीम कोर्ट केवल कानून की व्याख्या नहीं कर रहा, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दे रहा है, जिसकी समाज को बहुत जरूरत है। न्यायालय का संदेशस्पष्ट है कि न्याय समय पर मिले, जीवन सुरक्षित रहे, महिलाओं का सम्मान हो और लोकतंत्र मजबूत बने। न्याय में देरी केवल कानूनी समस्या नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकट भी पैदा करती है। जब किसी व्यक्ति को वर्षों तक न्याय नहीं मिलता, तो उसका कानून और संविधान पर विश्वास कमजोर होने लगता है। गरीब व्यक्ति अपनी जमा पूंजी वकीलों और अदालतों के चक्कर में खर्च कर देता है। कई बार आरोपी सजा से बच जाते हैं क्योंकि गवाह मर जाते हैं, सबूत कमजोर हो जाते हैं या पीड़ित ही हार मान लेता है। निर्भया रेप कांड को कौन नहीं जानता वह केस बड़ा लंबा चला और उसके माता-पिता को इंसाफ मिलने में बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी, यह इंसाफ बड़ी देरी से मिला था। विशेष रूप से हत्या, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बुजुर्गों के मामले, भूमि विवाद और आर्थिक अपराधों में तेजी से सुनवाई बहुत जरूरी है। कई बार पीड़ित परिवार वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष करता रहता है। यदि हाई कोर्टों को यह निर्देश दे दिए गए है तो पेंडिंग मामलों को प्राथमिकता देकर जल्दी समाप्त किया जाए, तो पीड़ितों का भरोसा मजबूत होगा।

कैसे कामयाब हुए डीके

आखिरकार इतनी लंबी जद्दोजहद सियासी उठापटक के बाद डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री की गद्दी पाने में कामयाब रहे। उन्हें बेंगलुरू की इस गद्दी पर काबिज करवाने में परोक्ष रूप से राहुल गांधी और पर्दे के पीछे से सोनिया व प्रियंका गांधी की एक महती भूमिका रही। जब इस दफे 2023 के विधानसभा चुनाव में धूमधड़ाके के साथ कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हुई तो कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता के समान बंटवारे का फार्मूला निकाला था, जिसके तहत सिद्धारमैया व डीके दोनों को ढाई-ढाई साल के टर्म के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था, बतौर सीनियर पहला मौका कांग्रेस के ओबीसी नेता सिद्धारमैया को मिला। जिनके ढाई साल का कार्यकाल 2025 के नवंबर में ही खत्म हो गया था, पर वे तब से ही डीके के पक्ष में गद्दी छोड़ने से आनाकानी कर रहे थे, जब उनके ऊपर दिल्ली ने दबाव बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपने विकल्प के तौर पर तीन नाम सुझाए, इसमें पहला नाम डॉ. जी परमेश्वरा का था जो एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, सिद्धारमैया की दूसरी पसंद एमबी पाटिल थे, जो येदियुरप्पा के बाद प्रदेश के एक बड़े लिंगायत नेता में शुमार होते हैं। सिद्धारमैया की तीसरी और आखिरी पसंद थे सतीश जारकीहोली, ये वाल्मीकि नायका समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, पर सिद्धारमैया की सुझाई लिस्ट में कहीं भी डीके का नाम नहीं था। सूत्रों की मानें तो डीके को गद्दी पर काबिज करवाने में गांधी परिवार की सबसे अहम भूमिका रही। समझा जाता है कि इससे पहले डीके की सोनिया गांधी से कई दौर की बातचीत पहले हो चुकी थी। इस बार कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की आहटों के बीच मां सोनिया के कहने पर राहुल ने सिद्धारमैया व डीके को सीधे दिल्ली तलब किया, उनसे वन-टू-वन बात की, यहां तक कि जिस मीटिंग में राहुल ने सिद्धारमैया से दो टूक डीके के लिए गद्दी छोड़ने को कहा उस मीटिंग में राहुल-डीके व सिद्धारमैया बस यही तीन लोग मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल व अजय माकन से पहले ही राहुल ने वहां से चले जाने को कहा था। लिहाजा अब तो तय हो ही गया है कि कर्नाटक के 25वें सीएम के तौर पर डीके अपने साथी 10 मंत्रियों के साथ 3 जून को शपथ ले सकते हैं, उनके मंत्रिमंडल का अगला विस्तार 18 जून को संपन्न होने वाले राज्यसभा चुनावों के बाद हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान के दबाव में भले ही इस गुरुवार को कर्नाटक के कद्दावर ओबीसी नेता सिद्धारमैया ने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को अलविदा कह दिया हो, पर अभी वे दिल्ली से अपने इस त्याग का प्रतिदान चाहते हैं। सूत्रों की मानें तो अभी-अभी जब सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी मांगों की एक विस्तृत सूची उनके हवाले की है। सूत्र बताते है कि सिद्धारमैया की सबसे बड़ी चिंता अपने पुत्र यतीन्द्र सिद्धारमैया को लेकर है, वे चाहते हैं कि डीके कैबिनेट में यतीन्द को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले, मुमकिन हो तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने आने वाले राज्यसभा व विधान परिषद में होने वाली नियुक्तियों के लिए अपने पसंदीदा नेताओं के नाम सुझाए हैं, इसके अलावा डीके के मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे के लिए भी बतौर मंत्री उन्होंने अपने करीबी नेताओं के नाम सुझाए हैं। सीधे तौर पर सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं के लिए अहम मंत्रालयों के लिए पैरवी की है। सिद्धारमैया इस बार जब दिल्ली आए तो अपने एमएलसी पुत्र यतीन्द्र को वे साथ-साथ लेकर घूमे। उन्होंने अपने पुत्र को राहुल गांधी से मिलवाया। फिर वे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे व कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे। अभी-अभी तो बकरीद की खुशियों ताजा-ताजा माहौल में लिपटी थी कि जम्मू-कश्मीर के नाराज कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा वर्ग 'दिल्ली चलो' के आह्वान के लिए कमर कसने लगा है। ये नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर भाजपा-पीडीपी के स्लीपर सेल के कब्जे का आरोप लगा रहे हैं और अपने शीर्ष नेताओं से जानना चाह रहे हैं कि 'मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में अपने सहयोगी दल कांग्रेस को पूरी तरह नजरअंदाज क्यों किया हुआ है और अब्दुल्ला की इस हरकत पर प्रदेश के शीर्ष कांग्रेसी नेता खामोश क्यों हैं' राहुल गांधी की निजी पसंद में शुमार होने वाले यहां के प्रदेश कांग्रेस प्रमुख तारिक हामिद कर्रा अपने दो वर्षों का कार्यकाल एक गुमनामी में पूरा कर चुके हैं, जम्मू-कश्मीर के एआईसीसी प्रभारी सैय्यद नासिर हुसैन, जो खड़गे की निजी पसंद के तौर पर उभरे हैं, वे भी एक तरह से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए अबूझ बने हुए हैं। सो, यहां पार्टी के अंदर गुटबाजी ने पूरी तरह सिर उठा लिया है। अब जबकि दिल्ली अपने प्रदेश के इन नेताओं की आवाजों पर कान नहीं धर रही है तो पीसीसी के वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक रैलियां निकाल खुलेआम कर्रा व हुसैन दोनों को निशाने पर ले रहा है।

सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व पीसीसी प्रमुख विकार रसूल वानी इस असंतुष्ट मोर्चे का सामने से नेतृत्व कर रहे हैं। स्मरण रहे कि रसूल वानी को पिछले विधानसभा चुनावों के बीच बिना किसी जरूरी औपचारिकता के हटा दिया गया था ताकि उनकी जगह राहुल गांधी कर्रा को ला सकें। राज्यसभा की रिक्त 26 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव आहूत है। 3 सीटें मध्य प्रदेश से भी खाली हो रही हैं जिसमें से 2 भाजपा की और एक सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। कांग्रेस की यह सीट वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की रिक्त हो रही है। वे दो बार से राज्यसभा में हैं, इस बार उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। सूत्रों की मानें तो दिग्विजय चाहते हैं कि 'आलाकमान उनकी जगह इस बार उनकी फक्कड़ पार्टी को इस सीट से उपकृत कर दे।' वहीं प्रदेश के एक और कद्दावर कांग्रेसी नेता कमलनाथ भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कमलनाथ का कहना है कि 'अगर मुझे नहीं भेजना चाहते तो मेरे पुत्र नकुलनाथ को इस सीट से उपरी सदन में भेज दिया जाए।' पर पार्टी में कमलनाथ व नकुलनाथ दोनों का पुरजोर विरोध है। नकुलनाथ के बारे में पार्टी के कुछ नेता खुल कर कह रहे हैं कि 'वे 2024 में भाजपा के सीधे संपर्क में थे और उनकी भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं भी तब बेहद आम थीं।' पार्टी के कुछ नेताओं का मत है कि 'इस सीट से किसी दलित नेता को ऊपरी सदन में भेजा जाना चाहिए।' वहीं इस सीट के लिए जीतू पटवारी, अरुण यादव और मीनाक्षी नटराजन के नामों की भी चर्चा है। मीनाक्षी मंदसौर से 2009-14 के काल में लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं, फिलहाल वह तेलंगाना की प्रदेश प्रभारी भी हैं। इन्हें राहुल गांधी की निजी पसंद के तौर पर देखा जाता है। बंगाल फतह के बाद अब भाजपा का सारा फोकस पंजाब पर सिमट आया है, यहां भी अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब भाजपा के पहले सिख प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति के मात्र एक दिन बाद आए यहां के स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों ने भाजपा कैडर को एक नई संजीवनी देने के काम किया है।

इन चुनाव परिणामों ने संकेत दिया है कि 'राज्य के शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में निरंतर भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा है। वर्ष 2021 में जहां भाजपा केवल 49 वार्ड जीत पाई थी, इस बार पार्टी की जीत का आंकड़ा 170 से ज्यादा वार्डों को भी पार कर गया। हालांकि इसके बावजूद कुल वार्डों के लिहाज से भाजपा आप, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल व निर्दलीय के बाद पांचवें स्थान पर रही, पर यह प्रदर्शन भी कहीं न कहीं पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार की ओर ही इशारा कर रहा है। दरअसल, इस बार यहां भाजपा की सफलता केवल पारंपरिक हिंदू बहुल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मोहाली, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, मानसा, पटियाला और फाजिल्का जैसे जिलों की नगर परिषदों और नगर पंचायतों में भी पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति का अहसास दर्ज कराया है।

> नकुलनाथ के बारे में पार्टी के कुछ नेता खुल कर कह रहे हैं कि 'वे 2024 में भाजपा के सीधे संपर्क में थे और उनकी भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं भी तब बेहद आम थीं।' पार्टी के कुछ नेताओं का मत है कि 'इस सीट से किसी दलित नेता को ऊपरी सदन में भेजा जाना चाहिए।' वहीं इस सीट के लिए जीतू पटवारी, अरुण यादव और मीनाक्षी नटराजन के नामों की भी चर्चा है। मीनाक्षी मंदसौर से 2009-14 के काल में लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं, फिलहाल वह तेलंगाना की प्रदेश प्रभारी भी हैं। इन्हें राहुल गांधी की निजी पसंद के तौर पर देखा जाता है। बंगाल फतह के बाद अब भाजपा का सारा फोकस पंजाब पर सिमट आया है, यहां भी अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री के लिए प्रोटोकॉल ताक पर

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो पिछले सप्ताह भारत के दौरे पर थे। वे जब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरे तो वहां की तस्वीरें देख कर भाजपा के इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया में बढ़-चढ़ कर प्रचारित किया कि भारत ने अमेरिका को औकात बता दी। अमेरिकी विदेश मंत्री की अगवानी करने सिर्फ अमेरिकी राजदूत और भारत सरकार के दो जूनियर अधिकारी पहुंचे थे। सवाल है कि क्या किसी देश का विदेश मंत्री आता है तो भारत के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री उसको रिसीव करने जाते हैं प्रोटोकॉल के तहत ही रुबियो को हवाईअड्डे पर रिसीव किया गया। लेकिन उसके बाद जो हुई वह अभूतपूर्व था। अमेरिकी विदेश मंत्री हवाई अड्डे से निकले और दनदनाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। ऐसा लग रहा है, जैसे वहां प्रधानमंत्री पलक पांवड़े बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे। वहां रुबियो ने प्रधानमंत्री के साथ एक घंटे तक दोपक्षीय वार्ता की, जिसके बारे में बताया गया कि ऊर्जा सुरक्षा से लेकर तकनीक, व्यापार और पश्चिम एशिया के संकट के बारे में बात हुई। सोचने वाली बात है कि यह प्रोटोकॉल का कितना बड़ा उल्लंघन है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी देश के विदेश मंत्री के साथ दोपक्षीय वार्ता कर रहा है आमतौर पर किसी देश का विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आता है या भारत के विदेश मंत्री किसी देश के दौरे पर जाते है तो उनकी बात अपने समकक्ष से होती है। इस लिहाज से रुबियो की बात जयशंकर से होनी चाहिए थी। ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रधानमंत्री किसी देश के विदेश मंत्री के साथ दोपक्षीय वार्ता करे।

भाजपा का ऑपरेशन केरलम शुरू

भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन केरलम शुरू हो गया है। उसे लग रहा है कि जब तक केरलम में त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी और लेफ्ट की मौजूदगी बनी रहेगी तब तक भाजपा के लिए स्कोप नहीं बनेगा। दो चुनावों में उसने देख लिया है कि उसका वोट 12 फीसदी से ऊपर नहीं जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जरूर थोड़ा ज्यादा वोट मिला लेकिन विधानसभा में केरलम के लोग अब भी कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन के बीच रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स के साथ है। भाजपा को यह भी पता है कि केरलम के 55 फीसदी हिंदू मतदाताओं में से ज्यादातर का रुझान लेफ्ट यानी सीपीएम गठबंधन की ओर है। इसीलिए ऑपरेशन केरलम के तहत सीपीएम को निशाना बनाया गया है। राज्य में सीपीएम के सबसे बड़े नेता और लगातार दो बार मुख्यमंत्री रहे पिनरायी विजयन के यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापे से इसका संकेत मिलता है। यह मामला विजयन की बेटी की कंपनी से जुड़ा है। विजयन पर यह आरोप पहले लगा था कि उन्होंने अपनी बेटी वीणा के पति को राज्य सरकार में मंत्री बनाया। फिर वीणा की कंपनी को बिना काम कराए भुगतान का मामला आया। अगर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप से लेफ्ट कमजोर होता है तो अपने आप भाजपा के लिए जगह बनेगी। गौरतलब है कि लेफ्ट नेताओं खास कर विजयन के हिंदू वोटरों पर ज्यादा फोकस करने का नुकसान लेफ्ट को हुआ। ईसाई और मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर गोलबंद हुआ। अगर हिंदू वोट लेफ्ट से टूट कर भाजपा की ओर आता है तो भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला बनेगा, जिसमें भाजपा को फायदे की संभावना दिख रही है।

तमिलनाडु में अन्ना डीएमके पर खतरा

आमतौर पर विपक्षी पार्टियां अपने विधायकों-सांसदों को भाजपा द्वारा तोड़े जाने को ऑपरेशन लोटस ही कहती हैं। अब तमिलनाडु में इसी तर्ज पर एक ऑपरेशन की चर्चा है, जिसका नाम है ऑपरेशन एल'। यहां एल' का मतलब है लॉटरी या लीमा या लीव। इस ऑपरेशन के चलते ई. पलानीसामी की पार्टी अन्ना डीएमके का अस्तित्व खतरे में है। पहले तो विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद उसके 47 में से 30 विधायकों ने बगावत कर विश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को समर्थन दे दिया। अब बचे 17 में से चार विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। ये चारों विधायक अब विजय की पार्टी टीवीके में शामिल होकर उसके टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। सबसे ज्यादा दिलचस्प मामला लॉटरी और लीमा का है। गौरतलब है कि लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन की पत्नी का नाम लीमा रोज मार्टिन है। वे अन्ना डीएमके की टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीती हैं। उनके दामाद आधव अर्जुन टीवीके के नेता है और विजय की सरकार में मंत्री है। माना जा रहा है कि आधव अर्जुन और उनकी सास लीमा रोज मार्टिन अन्ना डीएमके को तोड़ने का अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का मकसद टीवीके को अकेले दम पर बहुमत दिलाना है। अभी टीवीके की 107 सीटें हैं। मुख्यमंत्री विजय दो सीटों से जीते थे। एक सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सो, अब पांच सीटें खाली हैं, जिन पर उपचुनाव होगा। जल्दी ही कुछ और विधायकों का इस्तीफा होगा। बहुमत का आंकड़ा 118 का है। यानी कम से कम 11 सीटें और जीतने की जरूरत है।

अब यूपीएससी के छात्रों की परेशानी

समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार और उसकी एजेंसियां शिक्षा व छात्रों के साथ क्या करना चाहती है 12वीं की परीक्षा में कॉपियों की दोबारा जांच के चक्कर में इस समय लाखों छात्र भटक रहे हैं तो नीट के करीब 23 लाख छात्रों की किस्मत भी अधर में लटका दी गई है। अब सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे है। रविवार, 24 मई को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की आईएएस, आईपीएस सहित दूसरी केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद ही प्रश्न पत्र को लेकर सवाल उठने लगे। ऐसा लग रहा है कि सारे प्रयोग सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ही करना चाहती है। बताया जा रहा है कि इस साल यूपीएससी का पेपर इतना भारी था कि ज्यादातर छात्रों को समझ ही नहीं आया। इतना मुश्किल पेपर सेट करने के फैसले का बचाव करते हुए कई लोगों ने कहा कि छात्रों को कोचिंग सेंटर वालों के चंगुल से बचाने के लिए इस तरह का पेपर सेट किया गया। लेकिन ज्यादातर लोगों ने लिखा कि इस बार यूपीएससी बनाम अभ्यर्थी हो गया था। यह भी कहा गया कि अगर पेपर सेट करने वालों को भी इस परीक्षा में बैठा दिया जाता तो वे 30 फीसदी से ज्यादा सवाल नहीं हल कर पाते।

कांग्रेस बंगाल में शहीद दिवस पर दावा करेगी

ममता बनर्जी भले कह रही हैं कि जून में विपक्षी गठबंधन की बैठक होगी। उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ फिर से सद्भाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी उनके साथ सद्भाव दिखाने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस ने झंडा बुलंद किया है। प्रदेश कांग्रेस के नेता तृणमूल के जिला व पंचायत स्तर के कई कार्यालयों पर कांग्रेस का झंडा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब पहले कांग्रेस के कार्यालय थे, जिन पर ममता बनर्जी की पार्टी ने कब्जा कर लिया था। इस बीच खबर है कि ममता बनर्जी हर साल शहीद दिवस का जो कार्यक्रम करती है, उस पर भी कांग्रेस दावा करेगी। गौरतलब है कि 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन के दौरान कोलकाता में युवा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

हरियाणा सरकार गुरुग्राम में 'मेक इन हरियाणा' पॉलिसी और 9 नई सेक्टरल पॉलिसी करेगी लॉन्च

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में होगा आयोजन

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार 1 जून, 2026 को गुरुग्राम में आयोजित होने वाले एक बड़े उद्योग एवं निवेश कार्यक्रम में अपनी फ्लैगशिप 'मेक इन हरियाणा' पॉलिसी के साथ 9 नई सेक्टरल पॉलिसियों का शुभारंभ करेगी। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और उद्योग एवं वाणिय मंत्री राव नरबीर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निवेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विदेशी प्रतिनिधिमंडल तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारक भाग लेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नई पॉलिसी रूपरेखा हरियाणा को देश के अग्रणी विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और निवेश गंतव्य के रूप में और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में तैयार की गई है। इन नीतियों का उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना, क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, एमएसएमई को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसर सृजित करना, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना तथा भविष्य उन्मुख औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया जाएगा, जो हरियाणा की औद्योगिक प्रगति और भविष्य की विकास दृष्टि में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। प्रवक्ता ने बताया कि नई नीति व्यवस्था तेज़ और प्रभावी प्रशासन, उद्योगों के साथ मजबूत साझेदारी, सुदृढ़ औद्योगिक तंत्र तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप विकास के प्रति हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मजबूत कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक राजनीतिक पहुंच, विश्वस्तरीय अवसंरचना, परिपक्व औद्योगिक आधार तथा तेजी से विकसित हो रहे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के कारण हरियाणा ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, AVGC, फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस, खिलौना एवं खेल सामग्री निर्माण, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। कार्यक्रम के दौरान राय में औद्योगिक विकास और निवेशक सुविधा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण नई घोषणाएं भी की जाएंगी। राय सरकार ने सक्रिय प्रशासन, निवेशक-केंद्रित सुविधा तंत्र और उद्योगोन्मुख सुधारों के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डेरा राधा स्वामी ब्यास में बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से की शिष्टाचार भेंट

(संवाददाता)

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को डेरा राधा स्वामी सत्संग, ब्यास पहुंचकर डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा विभिन्न सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचार-विमर्श किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कपूरथला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध माता भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश एवं देशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की

कपूरथला के माता भद्रकाली मंदिर में की पूजा-अर्चना

आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत समाज को जोड़ने तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कपूरथला के सर्कुलर रोड मार्केट क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की तथा स्थानीय नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों में मुख्यमंत्री के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों से कहा कि सरकार जनकल्याण, विकास और सुशासन के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है तथा आमजन के हित सर्वोपरि हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री तरुण भंडारी, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

देवी अहिल्याबाई होल्कर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज, राष्ट्र व संस्कृति के लिए किया समर्पित - हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष

(संवाददाता)

चण्डीगढ़ । हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण ने आज देवी अहिल्याबाई होल्कर की जयंती के अवसर जिला करनाल के गांव सदरपुर, रसूलपुर कलां और घरौंडा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने देवी अहिल्याबाई होल्कर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

अहिल्याबाई होलकर - संघर्ष और सशक्तिकरण की मिसाल

श्री हरविंदर कल्याण ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होल्कर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज, राष्ट्र व संस्कृति के लिए समर्पित किया। उन्होंने बेहद कठिन समय में, जब देश बाहरी आक्रमणों और कुरीतियों से जूझ रहा था, समाज और संस्कृति को बचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को त्यागकर शिक्षा और शासन की जिम्मेदारी संभाली और सोमनाथ मंदिर जैसी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार कर राष्ट्र की

संस्कृति को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि भारत सोने की चिड़िया थी। पहले मुगलों और अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा व इतिहास से महापुरूषों का नाम हटाकर संस्कृति को खत्म करने का काम किया।

महापुरुष किसी एक जाति के नहीं, पूरे समाज के होते हैं

श्री हरविंदर कल्याण ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को जातियों के बंधन से ऊपर उठाकर एक सूत्र में पिरोना है। उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी एक विशेष वर्ग या जाति के नहीं होते, बल्कि उनके विचार पूरी मानवता की धरोहर होते हैं।

जब 36 बिरादरी मिलकर ऐसे कार्यक्रम मनाती है तो समाज की एकता और अधिक मजबूत होती है।

युवाओं को सेवा भाव और मेहनत का दिया संदेश

महान विभूतियों के संस्कार और सेवा भाव को आत्मसात करे युवा पीढ़ी - हरविंदर कल्याण

विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी और बच्चों को महापुरुषों के विचारों से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी तरक्की केवल खुद तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आसपास कमजोर या गरीब को भी देखना चाहिए और उनके हित के कार्य करना चाहिए। उन्होंने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे साधारण और गरीब परिवारों से निकलकर इन विभूतियों ने मेहनत और ईमानदारी के बल पर देश के सर्वोच्च पदों को सुशोभित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार युवाओं को सफलता के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं - रणबीर गंगवा

चण्डीगढ़ । (संवाददाता) हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री का 'मन की बात' केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों से संवाद का प्रभावी माध्यम है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जनभागीदारी को बढ़ावा देता है। श्री रणबीर गंगवा ने रविवार को जिला हिसार के सातरोड खास स्थित बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के 134वें संस्करण को सामूहिक रूप से सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी विचार समाज और राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश को नई दिशा देने वाला है और उनके विचार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने विचारों के माध्यम से देशवासियों को सकारात्मक सोच, नवाचार, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचारों से युवा वर्ग प्रेरणा लेकर सफलता के पथ पर अग्रसर हो रहा है तथा राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

शहीदों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता - राव इंद्रजीत सिंह

चण्डीगढ़ । (संवाददाता) केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा संस्कृति राय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रविवार को रेवाड़ी जिला के गांव खण्डोडा में अमर शहीद अरुण कुमार यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। शहीद अरुण कुमार यादव सिक्किम में ड्यूटी के दौरान आई प्राकृतिक आपदा में आमजन और अपने साथियों को बचाने के प्रयास में अपने शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए 4 अक्तूबर,2023 को देश सेवा करते हुए शहीद हो गए। इस अवसर पर विशेष रूप से बावल के विधायक डॉ. कृष्ण कुमार, कोसली के विधायक अनिल यादव व भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली विशेष रूप से मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री ने गांवों के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की।

राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि शहीद अरुण कुमार यादव ने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनको अपना सर्वश्रेष्ठ

देने के लिए सेना द्वारा 8 मेडल भी प्रदान किए गए जो इनके अदम्य साहस को दर्शाते है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के तहत लेबनान देश में एक साल साहस और वीरता के साथ अपनी सेवाएं भी दी। देशवासी उनके बलिदान को सदैव स्मरण रखेंगे और आने वाली पीढ़ियां उनसे राष्ट्रभक्ति एवं कर्तव्यनिष्ठ की प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमेशा से ही दक्षिण हरियाणा के युवा सेना में भर्ती होकर देश की हिफाजत के लिए आगे रहे हैं। उन्होंने उन माताओं-बहनों की भी सराहना की जिन्होंने अपने बच्चों और भाइयों को सेना में भर्ती कर देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने शहीद अरुण कुमार यादव की माता, पत्नी और बच्चों को भी विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है।

समारोह के दौरान ग्रामीणों द्वारा राजकीय विद्यालय का नामकरण शहीद अरुण कुमार यादव के नाम पर करने, गांव के जोहड़ों को नहरी पानी से जोड़ने तथा अन्य विकासात्मक मांगों का ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विषयों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

दिल्ली में इमारत गिरने का वीडियो आया सामने- बम फटने जैसी आई आवाज, धूल-चीखें और मची अफरा-तफरी, चार लोगों की मौत

नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली के साकेत में शनिवार को इमारत गिरने के हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 घायल हो गए हैं। घायलों में तीन महिला और सात पुरुष हैं। वहीं पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मालिक को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। हादसा उस वक्त हुआ जब सातवीं मंजिल को छत डालने की तैयारी हो रही थी। वेस्टर्न मार्ग स्थित गली नंबर-5 में हुई। हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इमारत भरभराकर गिरती नजर आ रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इमारत एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, जिसकी पहली और दूसरी मंजिल पर कई निजी कार्यालय थे। घटना के समय पास के एक प्लॉट पर बनी रसोई में कुछ मेडिकल छात्र मौजूद थे। जब इमारत का मलबा उस पर गिरा, जिससे रसोई भी ढह गई। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह तक दमकल विभाग, एनडीआरएफ, डीडीएमए और स्थानीय पुलिस की मदद से मलबे से 14 लोगों को बाहर निकाला गया। सभी को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में से एक की पहचान 26 वर्षीय रवि के रूप में हुई है। घायलों में आठ लोगों की पहचान गुरुग्राम के 26 साल के तरुण कुमार, बिहार की 27 साल की साइका खान, मैदुल्लाजाब की 25 साल की नीलम यादव, मैदुल्लाजाब के 24 साल के आदित्य शर्मा, नोएडा के 25 साल के शितिज प्रताप, साकेत के 25 साल के अनुज दीक्षित, मैदुल्लाजाब की 25 साल की आस्था और साकेत के 24 साल के विशाल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घायलों में ज्यादातर छात्र थे, जो पास में रहने वाले मेडिकल छात्रों के लिए बनी रसोई में खाना खा रहे थे। जब इमारत गिरी, तो कुछ लोग उसके अंदर भी मौजूद थे। अधिकारी ने बताया कि बचाव और तलाशी अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि मलबे के नीचे कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय पुलिस अन्य बचाव टीमों के साथ मिलकर अभी भी काम में जुटी हुई है। मैदुल्लाजाब में शनिवार रात जब तीन मंजिला इमारत भरभराकर गिरी, तब कुछ मिनटों तक पूरे इलाके में सिर्फ धूल, चीखें और अफरा-तफरी थी। लेकिन इसी अफरातफरी के बीच सबसे पहले जो चीज दिखाई दी, वह थी स्थानीय लोगों की इंसानियत और हिम्मत।

हादसे के कुछ ही मिनटों में आसपास रहने वाले लोग अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे की ओर दौड़ पड़े। जोरदार आवाज सुनकर लोग घबराकर जब घरों से बाहर निकले, लेकिन धूल के गुबार के बीच किसी को समझ में नहीं आया। कई युवक तुरंत मलबे की तरफ भागे। उस समय तक न पुलिस पहुंची थी और न ही दमकल की टीमें। मलबे के भीतर से दबे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, तो कोई धीरे-धीरे कराह रहा था। इन्हीं आवाजों ने स्थानीय लोगों को रुकने नहीं दिया। किसी ने हाथों से ईंट हटानी शुरू की, तो कोई लोहे की सरियों को खींचकर रास्ता बनाने लगा। आसपास की दुकानों और घरों से फावड़े, रॉड और टॉर्च तक उठा लाए गए। स्थानीय निवासी जगदीश बताते हैं कि उस वक्त किसी के दिमाग में अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं था। इसी दौरान मलबे में दबे कुछ लोगों ने आवाज देकर अपनी मौजूदगी का संकेत दिया। लोगों ने तेजी दिखाई और सहत एजेंसियों के पहुंचने से पहले ही तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी-ममता बनर्जी

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुगली में हमला हुआ है। कल्याण बनर्जी आज टीएमसी कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए ज्ञापन देने गए थे।

दावा किया गया है कि उसी दौरान उन पर हमला हुआ। गौरतलब है कि कल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी हमला हुआ था। सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का मुक्की हुई और उनके कपड़े फाड़ दिए गए।

इस दौरान उन पर अंडे फेंके गए और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कल्याण बनर्जी रविवार को हुगली के चंडीतला पुलिस स्टेशन में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस दौरान उनका विरोध शुरू हो गया और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कथित तौर पर उन पर हमला किया गया। जिससे उनके सिर में चोट आने का दावा

किया गया है। कल्याण बनर्जी के खिलाफ भी चोर-चोर के नारे लगाए गए।

हमले के बाद कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को नियंत्रित किया। हमले के बाद मीडिया से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चंडीतला थाना प्रभारी से मुलाकात करने और ज्ञापन सौंपने जाते समय उन पर हमला किया गया। उन्होंने दावा किया कि यह घटना उनकी हत्या की कोशिश थी। बनर्जी ने कहा, चंडीतला थाने के प्रभारी अधिकारी से मिलने और ज्ञापन देने के लिए मैं कार से जा रहा था। चंडीतला बाजार में भारी ट्रैफिक जाम होने के कारण मैं अपने पीएसओ के साथ चंडीतला क्रॉसिंग पर पैदल चल रहा था, जो चंडीतला थाने से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। उन्होंने आरोप लगाया, इसी दौरान भगवा कपड़े पहने 10-15 भाजपा समर्थकों ने अचानक नारेबाजी शुरू कर दी और तनावपूर्ण माहौल बना दिया। वे मुझे गालियां दे रहे थे, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। तभी किसी ने मेरे सिर पर पत्थर फेंका। उन्होंने कहा, मैं सड़क पर गिर पड़ा। उस समय सीआरपीएफ के एक जवान ने मुझे बचाया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। बनर्जी ने राज्य पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा, पश्चिम बंगाल पुलिस पूरी तरह खामोश रही और मूकदर्शक बनी रही। उसने यह सब होने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। यहां पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। यह घटना मेरी हत्या की कोशिश थी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी उनसे मिलने पहुंचीं।

अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला, कहा- 2027 के चुनावों में भाजपा की सारी तिकड़म निकाल देगी जनता

लखनऊ । समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा पर अनैतिक तरीकों से चुनाव जीतने का आरोप लगाया और दावा किया कि लोग भविष्य के चुनावों में पार्टी की राजनीतिक चालों को नाकाम कर देंगे। यादव ने यह बात भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के सोमवार के एक बयान के जवाब में कही।

सपा का आरोप- भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है

प्रकाश ने कहा था कि चुनाव केवल विकास के आधार पर नहीं जीते जाते, बल्कि तिकड़म और रणनीति के माध्यम से भी जीते जाते हैं। भाजपा विधायक के इस बयान का खोंडियो एक्स पर साझा करते हुए यादव ने पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, "भाजपा में जितना अधिक बेईमान व्यक्ति होता है, वह उतना ही ऊंचा पद पाता है। उन्होंने कहा, भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है, इस बात को स्वीकार करके भाजपा के विधायक ने भ्रष्ट भाजपाई राजनीति का एनकाउंटर कर दिया है, साथ ही उसके ऊपर बुलडोज़र भी चलवा दिया है।

2027 के चुनावों में बीजेपी को खारिज कर देगी जनता

सपा प्रमुख ने यह सवाल भी किया कि देखते हैं कि भाजपा इस विधायक के बयान पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने कहा, अब देखना होगा कि क्या इस भाजपा विधायक को पार्टी से निकाला जाएगा या अगले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। यादव ने दावा किया कि भाजपा को 2027 के चुनावों में खारिज कर देंगे। यादव ने दावा किया "इस बार जनता भाजपा की सारी तिकड़म निकाल देगी। भाजपा हारेगी और फिर कभी नहीं आएगी। गौरतलब है कि हरदोई जिले के गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रकाश ने कहा था कि चुनाव विकास से नहीं, तिकड़म से जीते जाते हैं। टड़ियावां ब्लॉक में प्रधानों के कार्यकाल में छह माह की वृद्धि होने पर शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में प्रधानों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा, चुनाव केवल विकास कार्यों के आधार पर नहीं जीते जाते। राजनीतिक तिकड़म और रणनीति भी अहम भूमिका निभाती है। प्रकाश ने प्रधानों से आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी करने को कहा। उन्होंने कहा, साम, दाम, दंड, भेद जो भी तिकड़म कर पाना कर लेना, लेकिन अगला चुनाव जीतना है।

बकरीद पर सूर्या की निर्मम हत्या करने वाला असद एनकाउंटर में ढेर

साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद पर हुई युवक की हत्या के मामले में हत्यारोपित और पुलिस के बीच शनिवार देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी ढेर हो गया। जबकि उसका साथी पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में 28 मई को बकरीद के दिन मुस्लिम युवक असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। आरोपित पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। शनिवार देर रात पुलिस टीम वसुंधरा क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। तभी असद अपने एक साथी के साथ आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। जिसके बाद आरोपित ने उस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली उसके जा लगी। उसका साथी मौके से फरार हो गया। असद को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक के विवाद में सूर्या की चाकू से गोदकर हत्या की गई। आरोपित असद ने नई बाइक ली थी, इसे सूर्या ने चलाने के लिए मांगा। बाइक न देने पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भीषण गर्मी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड में समाज सेवा, जल संरक्षण, खेल, भीषण गर्मी से बचाव और भारत में आम की विविधता जैसे कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने लोगों से समाजहित के कार्यों में भागीदारी बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानना, उनकी सराहना करना और उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो लोगों को किसी अच्छे सामाजिक कार्य का हिस्सा भी बनना चाहिए। उनके अनुसार निस्वार्थ सेवा की कहानियां समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। गर्मी के मौसम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में मिलने वाले आमों की विशेषताओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस

(अल्फांसो), गुजरात का केसर, उत्तर प्रदेश का दशहरी और काशी का लंगड़ा आम अपनी अलग पहचान रखते हैं। उन्होंने आम की खेती से जुड़े किसानों की सराहना करते हुए कहा कि वे देश की कृषि अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान दे रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मौसम में पर्याप्त पानी पीना, धूप में निकलते समय सतर्क रहना और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रिय पारंपरिक पेयों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में आम पन्ना, पंजाब और हरियाणा में लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, बिहार-झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू शरबत काफी लोकप्रिय है। वहीं कोंकण और गोवा में कोकम शरबत तथा सोलकढ़ी, जबकि दक्षिण भारत में पनकम, नीर मोर और सांभरम जैसे पेय प्रचलित हैं। उन्होंने कहा कि ये पारंपरिक पेय केवल गर्मी से राहत नहीं देते, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को भी दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने देशभर में नदियों, तालाबों और कुओं के संरक्षण तथा पुनर्जीवन के लिए किए जा रहे सामुदायिक प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बचपन की यादों से जुड़े जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना विशेष संतोष और खुशी देता है। ऐसे प्रयास जल संरक्षण के साथ-साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ाते हैं।

सादगी से होगा डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण समारोह

महंगाई के चलते कांग्रेस ने भव्य आयोजन किया रद्द

नई दिल्ली । डीके शिवकुमार 3 जून को दोपहर 3.30 बजे राजभवन के ग्लास हाउस में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पार्टी नेताओं ने बताया कि यह तारीख और समय डीके शिवकुमार के निजी ज्योतिषी बेलूर द्वारकानाथ से सलाह-मशविरा करने के बाद तय किया गया है। ज्योतिष में गहरी आस्था रखने वाले डीके शिवकुमार को सलाह दी गई थी कि वे उस दिन शाम करीब 4.05 बजे शुरू होने वाले शुभ मुहूर्त में शपथ लें। इस समय को चुनने की एक वजह यह भी है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आसानी से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राज्य में नेतृत्व बदलाव को बातचीत के आखिरी दौर में प्रियंका गांधी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इस मौके की बड़ी राजनीतिक अहमियत होने के बावजूद कांग्रेस ने कोई भव्य या बड़ा आयोजन न करने का फैसला किया है। राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जॉर्ज चंद्रशेखर ने बताया, हमने पहले इस कार्यक्रम को विधान सौध की भव्य सीढ़ियों पर करने का सोचा था, जिसमें 15,000 से 20,000 लोग

आते। लेकिन बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों से लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए हमने बड़ा कार्यक्रम रद्द कर दिया। जॉर्ज चंद्रशेखर ने आगे कहा कि खुद डीके शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम बिल्कुल साधारण होना चाहिए, जिससे जनता की सेवा के प्रति पार्टी का लगाव दिखे। चूंकि 3 जून को कामकाज का दिन है, इसलिए पार्टी जनता को होने वाली किसी भी तरह की ट्रैफिक जाम या असुविधा से बचाना चाहती थी।

बेंगलुरु लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन

गुजरात को 5 विकेट से हराया; कोहली ने छक्का लगाकर जीत दिलाई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विराट कोहली के नाबाद अर्द्धशतक के दम पर बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को उसकी के घर पर 5 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु आईपीएल इतिहास की तीसरी टीम बनी है, जो अपने खिताब को डिफेंड करने में सफल हुई है। बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की पारी खेली। 17 साल तक आईपीएल खिताब का इंतजार करने वाली आरसीबी का यह लगातार दूसरा खिताब है। आरसीबी को आईपीएल 2026 का चैंपियन बनने के लिए गुजरात ने 156 रन का लक्ष्य दिया था। वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने आरसीबी को तेज शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 4.3 ओवर में 62 रन की साझेदारी की। अय्यर 16 गेंदों पर 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 32 रन बनाकर आउट हुए, इसके बाद देवदत्त पडिक्कल (1), कप्तान रजत पाटीदार (15) और करुणाल पांड्या (1) का विकेट जल्दी-जल्दी गिरा. 62 पर 1 विकेट वाली आरसीबी ने 89 पर 3 विकेट गंवा दिए थे. विराट कोहली एक छोर पर डटे रहे. चौथे विकेट के लिए कोहली ने टिम डेविड के साथ 41 रन की अहम साझेदारी की. डेविड

17 गेंदों पर 24 रन की अहम पारी खेलकर आउट हुए, विराट कोहली अब भी क्रीज पर मौजूद रहे. 25 गेंदों पर विराट ने अपना अर्धशतक पूरा किया. यह विराट का आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक था. विराट ने 42 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से नाबाद 75 रन की पारी खेली. इससे पहले, साई सुदर्शन के नाबाद अर्द्धशतक के दम पर गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 155 रन बनाए है. पूरे टूर्नामेंट में विपक्षी टीमों के लिए सिरदर्द साबित हुई गुजरात टाइटंस की साई सुदर्शन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी इस मैच में नहीं चली. शुभमन गिल 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार हुए. इसके बाद भुवी ने सुदर्शन का विकेट लिया, जो 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए. सुदर्शन और गिल पर पूरे टूर्नामेंट में निर्भर रही गुजरात की बल्लेबाजी इस अहम मैच में दोनों की असफलता के बाद पूरी तरह साधारण नजर आई. गुजरात ने लगातार विकेट गंवाए. वाशिंगटन सुंदर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जो आरसीबी के गेंदबाजों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सके और अंत तक नाबाद लौटे. सुंदर 37 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद लौटे. सुंदर की पारी की वजह से ही आरसीबी 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 तक पहुंच सकी. गुजरात के लिए निशांत सिंधु 18 गेंदों पर 20, जोस बटलर 23 गेंदों पर 19, अरशद खान 6 गेंदों पर 15 और राहुल तेवतिया 5 गेंदों पर 7, राशिद खान 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हुए. रबाडा 3 रन बनाकर नाबाद रहे. आरसीबी की गेंदबाजी पर गौर करें तो रसिख सलाम डार ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

गुजरात टाइटन्स- साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, करुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार।